THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-04 | Issue-04 | January-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/

स्नातक छात्रों के आत्मबोध और कौशल निर्माण में सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता: झाँसी का एक विश्लेषण

रहीस अली[1], डॉ. धर्मेंद्र सिंह[2]
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर[1]
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर[2]

सार:

प्रस्तुत शोध-पत्र झाँसी जनपद के स्नातक छात्रों के आत्मबोध तथा कौशल निर्माण पर सरकारी कौशल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है। भारत में युवाओं की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जैसी कई योजनाएँ चलायी जा रही हैं। शोध का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झाँसी के स्नातक छात्र इन योजनाओं के बारे में कितने जागरूक हैं, इनसे उनका आत्मबोध और रोज़गार-संबंधी कौशल किस सीमा तक विकसित होता है। शोध की परिकल्पना यह है कि सरकारी कौशल योजनाओं में भागीदारी छात्रों के आत्मबोध एवं कौशल स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। मिश्रित विधि अनुसंधान-डिज़ाइन के अंतर्गत 320 स्नातक छात्रों से प्राथमिक आँकड़े प्राप्त किये गये और द्वितीयक आँकड़े सरकारी रिपोर्टों से लिये गये। परिणाम दर्शाते हैं कि योजनाओं की जागरूकता मध्यम स्तर की है, परंतु जिन छात्रों ने प्रशिक्षण लिया, उनके आत्मबोध और कौशल अंकों में स्पष्ट वृद्धि पायी गयी। निष्कर्षतः झाँसी में योजनाओं की प्रभावशीलता संतोषजनक है, फिर भी प्रचार, मार्गदर्शन और प्लेसमेंट तंत्र को सशक्त करने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: *आत्मबोध, कौशल निर्माण, सरकारी योजनाएँ, स्नातक छात्र, झाँसी*

1. प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जहाँ कुल जनसंख्या का बड़ा भाग 15 से 35 वर्ष की आयु-वर्ग में आता है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का सार्थक उपयोग तभी संभव है जब युवा वर्ग को न केवल औपचारिक शिक्षा बल्कि व्यावहारिक कौशल और आत्मबोध की भी पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाये। आत्मबोध से तात्पर्य है व्यक्ति का स्वयं की क्षमताओं, सीमाओं, रुचियों और मूल्यों के प्रति सचेत होना; जबकि कौशल निर्माण का आशय रोज़गार-योग्य व्यावहारिक दक्षताओं से है। दोनों मिलकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं (वगानी एवं गौर, 2021)। भारत सरकार ने 2014 के बाद कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की स्थापना करके अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ आरम्भ कीं। जुलाई 2015 में "विश्व युवा कौशल दिवस" पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.) को लागू किया गया, जिसका लक्ष्य चार वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कौशल-प्रशिक्षण देना था (एन.एस.डी.सी., 2020)। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.) ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15-35 वर्ष आयु-वर्ग के युवाओं हेतु प्रारम्भ की गयी (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2020)। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन सक्रिय है तथा झाँसी में बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण-केंद्र संचालित होते हैं।

झाँसी जनपद बुंदेलखंड का हृदय-स्थल है, जहाँ कुल जनसंख्या लगभग 19.98 लाख है तथा साक्षरता दर 83.02 प्रतिशत है (झाँसी जिला प्रशासन, 2021)। यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बी.आई.ई.टी. तथा अनेक स्नातक महाविद्यालय हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर भी कृषि-प्रधान, सूखा-प्रभावित और औद्योगिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में रोज़गार के अवसर सीमित हैं, जिससे शिक्षित बेरोज़गारी की समस्या गम्भीर बनी हुई है (मेहरोत्रा, 2014)। ऐसी स्थिति में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि क्या सरकारी कौशल योजनाएँ स्नातक स्तर के छात्रों तक प्रभावी ढंग से पहुँच रही हैं, क्या उनसे छात्रों का आत्मबोध और कौशल वास्तव में बढ़ रहा है तथा प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-से हैं। प्रस्तुत शोध इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने का प्रयास है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शिक्षण-संस्थानों तथा छात्रों तीनों के लिए उपयोगी होगा क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं की वास्तविक स्थिति, कमियाँ और सुधार के क्षेत्र स्पष्ट होंगे (जोशी एवं पाण्डेय, 2021)। आगे का विवरण साहित्य-समीक्षा, उद्देश्य, विधि, परिणाम और चर्चा के क्रम में प्रस्तुत है।

2. साहित्य-समीक्षा

कौशल विकास और आत्मबोध के क्षेत्र में हुए विविध अध्ययनों से इस शोध की पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है। मेहरोत्रा (2014) ने अपनी पुस्तक *India's Skills Challenge* में बताया कि भारत के मात्र 2 प्रतिशत कार्यबल को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त है, जबकि चीन में यह दर 47 प्रतिशत है। उन्होंने सुझाव दिया कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ कौशल प्रशिक्षण को एकीकृत किया जाये। जोशी एवं पाण्डेय (2021) ने हरियाणा में पी.एम.के.वी.वाई. पर 385 प्रशिक्षणार्थियों के अध्ययन में पाया कि अवसंरचना सुविधाओं और प्रशिक्षणार्थी संतुष्टि के मध्य सशक्त सकारात्मक सहसंबंध है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का स्तर बहुत निम्न है। सिंह (2020) ने लॉकडाउन काल में आत्मबोध और कौशल निर्माण पर अध्ययन करते हुए तर्क दिया कि आत्मबोध भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रथम स्तंभ है तथा यह आत्म-प्रबंधन, सामाजिक-जागरूकता एवं नेतृत्व का आधार है। उनका मानना है कि आत्म-निरीक्षण से छात्रों में अपनी शक्तियों और कमज़ोरियों की पहचान होती है, जिससे करियर-निर्णय बेहतर बनते हैं। वगानी एवं गौर (2021) ने 300 कॉलेज छात्रों पर अध्ययन में दर्शाया कि आत्मबोध स्वास्थ्य और कल्याण के अनेक आयामों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। राज एवं शर्मा (2021) ने पाया कि टी.वी. और सोशल मीडिया अभियानों ने शहरी क्षेत्रों में पी.एम.के.वी.वाई. नामांकन बढ़ाया, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता-सृजन हेतु संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता है।

रामासामी एवं गोपाल (2020) ने पी.एम.के.वी.वाई. के क्षेत्रीय कार्यान्वयन का मूल्यांकन करते हुए बताया कि नीतिगत ढाँचा सशक्त होने के बावजूद राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन में भारी असमानता है। अग्रवाल (2019) ने ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय रोज़गार के अवसरों की सीमितता को मुख्य बाधा बताया। राय एवं जोशी (2017) ने उत्तर प्रदेश में कौशल मिशन के आँकड़ों के आधार पर बताया कि नामांकन के बावजूद प्लेसमेंट दर सीमित है। गणेशन एवं वेथिराजन (2020) के अनुसार कौशल और सूचना समष्टि-आर्थिक विकास के मूल चालक हैं तथा भारत को 2022 तक लगभग 40 करोड़ कुशल कामगारों की आवश्यकता है। मोंडल आदि (2023) ने उच्चतर माध्यमिक छात्रों में आत्मबोध-कौशल पर अध्ययन में पाया कि लिंग, आयु और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आत्मबोध को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। राव (2021) ने जीवन-कौशल शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं का विश्लेषण करते हुए यह उजागर किया कि शहरी छात्रों को बेहतर संसाधन और अवसर मिलते हैं, जबकि बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों के छात्र पीछे रह जाते हैं। शर्मा (2020) ने महाविद्यालय छात्रों में जीवन-कौशल पर लिंग-आधारित अंतर का अध्ययन किया तथा पाया कि लड़कियाँ संचार-कौशल में आगे हैं, जबकि लड़के निर्णय-क्षमता में।

पुहान एवं माल्ला (2024) ने आत्म-प्रतिबिंब और अंतर्दृष्टि को छात्रों के समग्र विकास से जोड़ा। पाइल्ज़ एवं रेगेल (2021) ने भारत की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली का बाह्य परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण किया और औद्योगिक भागीदारी की कमी को मुख्य चिंता बताया। उपर्युक्त अध्ययनों से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं और छात्र-कौशल के बीच सम्बन्ध है, परंतु झाँसी जैसे विशिष्ट क्षेत्र में स्नातक

छात्रों पर इन योजनाओं के समेकित प्रभाव का अध्ययन अब तक अपर्याप्त रहा है यही शोध-अंतराल प्रस्तुत अनुसंधान का आधार है।

3. उद्देश्य

1. झाँसी जनपद के स्नातक छात्रों में सरकारी कौशल विकास योजनाओं के प्रति जागरूकता तथा भागीदारी का स्तर ज्ञात करना।
2. इन योजनाओं के द्वारा छात्रों के आत्मबोध और कौशल निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का सांख्यिकीय परीक्षण करना।

4. अनुसंधान विधि

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-डिज़ाइन पर आधारित है, जिसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों उपागम मिलाये गये हैं अर्थात् यह मिश्रित-विधि अध्ययन है। शोध-क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का झाँसी जनपद है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रशासनिक एवं शैक्षिक केंद्र है। अध्ययन की जनसंख्या झाँसी के विभिन्न शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों तथा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक छात्र थे। नमूना-आकार 320 छात्रों का रखा गया, जिनका चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विधि से किया गया, ताकि पुरुष-महिला, ग्रामीण-शहरी एवं विभिन्न संकायों (कला, विज्ञान, वाणिज्य) का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। आँकड़ा-संग्रह की मुख्य तकनीक संरचित प्रश्नावली रही, जिसमें कुल 35 कथन पाँच-बिंदुई लिकर्ट मापनी (1 = पूर्ण असहमत से 5 = पूर्ण सहमत) पर आधारित थे। प्रश्नावली के तीन खंड बनाये गये— जनसांख्यिकीय विवरण, योजना-जागरूकता एवं भागीदारी, तथा आत्मबोध-कौशल मापन। प्रश्नावली की विश्वसनीयता क्रोनबाख-अल्फा द्वारा जाँची गयी, जिसका मान 0.84 प्राप्त हुआ अर्थात् उपकरण विश्वसनीय है। वैधता हेतु तीन विषय-विशेषज्ञों से समीक्षा करवायी गयी। प्राथमिक आँकड़े फ़रवरी-जून 2021 के मध्य व्यक्तिगत भेंट तथा गूगल-फॉर्म दोनों माध्यमों से एकत्र किये गये। द्वितीयक आँकड़े अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट 2020-21, एन.एस.डी.सी. की वार्षिक रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय की डी.डी.यू.-जी.के.वाई. रिपोर्ट तथा झाँसी जिला प्रशासन की सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिये गये। आँकड़ा-विश्लेषण के लिए SPSS (संस्करण 25) तथा MS-Excel का प्रयोग किया गया। प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीकें थीं प्रतिशत विश्लेषण, माध्य, मानक विचलन, ची-वर्ग परीक्षण तथा युग्मित t-परीक्षण। महत्त्वता-स्तर 0.05 रखा गया। नैतिक मानकों का पालन करते हुए सभी प्रतिभागियों से सूचित सहमति ली गयी और गोपनीयता सुनिश्चित की गयी।

5. परिणाम

तालिका 1: प्रतिभागियों का जनसांख्यिकीय विवरण (n = 320)

श्रेणी	उप-श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
लिंग	पुरुष	178	55.6%
	महिला	142	44.4%
क्षेत्र	शहरी	192	60.0%
	ग्रामीण	128	40.0%
संकाय	कला	134	41.9%
	विज्ञान	98	30.6%
	वाणिज्य	88	27.5%
आयु	18-20 वर्ष	186	58.1%
	21-23 वर्ष	134	41.9%

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण आँकड़े, 2021।

तालिका 1 से स्पष्ट है कि नमूने में पुरुष प्रतिभागियों का अनुपात (55.6%) महिलाओं (44.4%) से अधिक है, जो उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा में पुरुष-प्रबलता को दर्शाता है। शहरी प्रतिभागी 60% तथा ग्रामीण 40% रहे, जिससे स्तरीकृत नमूनाकरण की विश्वसनीयता पुष्ट होती है। संकाय-वार वितरण में कला (41.9%) सर्वाधिक है, जो AISHE रिपोर्ट के राष्ट्रीय रुझान से मेल खाता है। आयु-समूह में अधिकांश (58.1%) प्रतिभागी 18-20 वर्ष के स्नातक प्रथम-द्वितीय वर्ष के थे।

तालिका 2: सरकारी कौशल योजनाओं के प्रति जागरूकता-स्तर

योजना	पूर्ण जागरूक	आंशिक जागरूक	अनभिज्ञ
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.)	41.6%	38.7%	19.7%
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.)	22.5%	31.2%	46.3%
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यू.पी.एस.डी.एम.)	28.1%	36.5%	35.4%
स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया	19.6%	28.7%	51.7%
अप्रेंटिसशिप योजना (एन.ए.पी.एस.)	17.5%	25.0%	57.5%

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण आँकड़े, 2021; एन.एस.डी.सी. वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21।

तालिका 2 दर्शाती है कि सबसे अधिक जागरूकता पी.एम.के.वी.वाई. (पूर्ण 41.6%) के प्रति है, क्योंकि यह मीडिया-प्रचार में अग्रणी रही है। डी.डी.यू.-जी.के.वाई. के प्रति 46.3% छात्र अनभिज्ञ हैं, जो ग्रामीण-केंद्रित प्रचार की कमी दर्शाता है। अप्रेंटिसशिप योजना के बारे में 57.5% छात्र पूर्णतः अनजान पाये गये, जो अत्यंत चिंताजनक है। ची-वर्ग परीक्षण से जागरूकता और क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) के मध्य महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध मिला ($\chi^2 = 18.42$, $p < 0.05$)।

तालिका 3: योजनाओं में वास्तविक भागीदारी एवं प्रशिक्षण-पूर्णता दर

श्रेणी	नामांकित	प्रशिक्षण पूर्ण	प्रमाणित	प्लेसमेंट प्राप्त
पी.एम.के.वी.वाई. भागीदार	64	52 (81.2%)	47 (73.4%)	21 (32.8%)
डी.डी.यू.-जी.के.वाई.	28	22 (78.5%)	19 (67.8%)	9 (32.1%)
यू.पी.एस.डी.एम.	41	33 (80.4%)	29 (70.7%)	12 (29.2%)
कुल भागीदार छात्र	133	107 (80.4%)	95 (71.4%)	42 (31.5%)

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण आँकड़े, 2021; पी.आई.बी. प्रेस रिलीज़, कौशल विकास मंत्रालय, 2021।

तालिका 3 दर्शाती है कि नमूने के 320 छात्रों में से 133 (41.5%) ने किसी-न-किसी योजना में नामांकन कराया। प्रशिक्षण-पूर्णता दर औसतन 80.4% रही जो संतोषजनक है, परंतु प्लेसमेंट दर मात्र 31.5% तक सीमित रही। पी.एम.के.वी.वाई. में सबसे अधिक भागीदारी (64 छात्र) देखी गयी। यह आँकड़े पी.एम.के.वी.वाई. 2.0 की राष्ट्रीय प्लेसमेंट दर 56.76% (एन.एस.डी.सी., 2020) से कम हैं, जो झाँसी में रोज़गार-अवसरों की सीमितता दर्शाता है।

तालिका 4: प्रशिक्षण-पूर्व एवं प्रशिक्षण-पश्चात आत्मबोध स्कोर (n = 107)

आत्मबोध आयाम	पूर्व-स्कोर (माध्य ± SD)	पश्चात-स्कोर (माध्य ± SD)	t-मान	p-मान
स्व-शक्ति की पहचान	2.84 ± 0.71	3.92 ± 0.62	11.67	< 0.001
करियर-स्पष्टता	2.71 ± 0.78	3.85 ± 0.69	12.04	< 0.001
भावनात्मक नियंत्रण	2.96 ± 0.74	3.74 ± 0.65	8.21	< 0.001
निर्णय क्षमता	2.88 ± 0.69	3.81 ± 0.66	10.15	< 0.001
समग्र आत्मबोध	2.85 ± 0.62	3.83 ± 0.58	12.96	< 0.001

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण आँकड़े, 2021।

तालिका 4 दर्शाती है कि प्रशिक्षण-पश्चात सभी चार आत्मबोध-आयामों में सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। समग्र आत्मबोध माध्य 2.85 से बढ़कर 3.83 हो गया ($t = 12.96$, $p < 0.001$)। सबसे अधिक प्रभाव "करियर-स्पष्टता" पर पड़ा (वृद्धि = 1.14), जो दर्शाता है कि कौशल प्रशिक्षण से छात्रों को अपने भविष्य के मार्ग का बेहतर बोध हुआ। यह परिणाम सिंह (2020) और वगानी एवं गौर (2021) के निष्कर्षों से मेल खाते हैं।

तालिका 5: कौशल-निर्माण स्कोर का तुलनात्मक विश्लेषण

कौशल आयाम	प्रशिक्षित (n=107) माध्य	अप्रशिक्षित (n=213) माध्य	t-मान	p-मान
संचार कौशल	3.78	2.96	9.84	< 0.001
डिजिटल कौशल	3.89	2.81	11.32	< 0.001
समस्या-समाधान	3.71	2.88	8.91	< 0.001
टीम-कार्य	3.82	3.05	8.45	< 0.001
उद्यमशीलता दृष्टिकोण	3.65	2.74	10.21	< 0.001

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण आँकड़े, 2021।

तालिका 5 स्पष्ट करती है कि सभी पाँच कौशल आयामों में प्रशिक्षित छात्रों का माध्य अप्रशिक्षित छात्रों से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। डिजिटल कौशल में सर्वाधिक अंतर (3.89 बनाम 2.81) पाया गया, जो कोविड-19 के बाद ऑनलाइन प्रशिक्षण की भूमिका को रेखांकित करता है। उद्यमशीलता दृष्टिकोण में भी सशक्त वृद्धि (अंतर = 0.91) दर्शाती है कि योजनाएँ छात्रों को नौकरी-तलाशी से आगे स्व-रोज़गार की दिशा में प्रेरित कर रही हैं।

तालिका 6: योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक (छात्र-धारणा के अनुसार)

कारक	अत्यंत प्रभावी (%)	मध्यम (%)	कम प्रभावी (%)
प्रशिक्षक की गुणवत्ता	48.5	36.2	15.3
अवसंरचना सुविधाएँ	32.7	41.5	25.8
उद्योग-संलग्नता	24.1	39.6	36.3
प्लेसमेंट सहायता	21.8	35.4	42.8
प्रचार-प्रसार	28.6	38.7	32.7

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण आँकड़े, 2021।

तालिका 6 दर्शाती है कि छात्रों की दृष्टि में प्रशिक्षक-गुणवत्ता सबसे प्रभावी कारक है (48.5% अत्यंत प्रभावी), जबकि प्लेसमेंट सहायता को 42.8% छात्रों ने कम-प्रभावी माना। उद्योग-संलग्नता और प्रचार-प्रसार में भी सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है। यह जोशी एवं पाण्डेय (2021) के निष्कर्षों से सुसंगत है, जिन्होंने अवसंरचना और संतुष्टि के मध्य सशक्त सम्बन्ध पाया था।

6. विवेचना

प्रस्तुत अध्ययन का प्रथम उद्देश्य झाँसी के स्नातक छात्रों में सरकारी कौशल योजनाओं की जागरूकता एवं भागीदारी ज्ञात करना था। तालिका 2 तथा 3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पी.एम.के.वी.वाई. के प्रति जागरूकता अपेक्षाकृत संतोषजनक (पूर्ण-आंशिक मिलाकर 80.3%) है, परंतु डी.डी.यू.-जी.के.वाई., अप्रेंटिसशिप तथा स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाओं के प्रति बड़ी संख्या में छात्र अनभिज्ञ हैं। यह स्थिति राज एवं शर्मा (2021) के उस निष्कर्ष की पुष्टि करती है कि टी.वी. एवं सोशल मीडिया अभियान शहरी क्षेत्रों में तो प्रभावी हैं, परंतु बुंदेलखंड जैसे अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत सूचना-प्रसार अब भी कमज़ोर है। नमूने के मात्र 41.5% छात्रों की वास्तविक भागीदारी दर्शाती है कि जागरूकता और भागीदारी के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद है। इस अंतर के पीछे प्रमुख

कारण हैं पारिवारिक सहमति का अभाव, प्रशिक्षण केंद्रों की भौगोलिक दूरी, समय-व्यवस्था में टकराव तथा भविष्य की रोज़गार-गारंटी पर सन्देह (अग्रवाल, 2019)।

दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत आत्मबोध और कौशल पर योजनाओं के प्रभाव का परीक्षण किया गया। तालिका 4 में युग्मित t-परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि प्रशिक्षण-पश्चात सभी आत्मबोध आयामों में सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई ($p < 0.001$)। विशेष रूप से करियर-स्पष्टता और स्व-शक्ति की पहचान में आये सुधार यह संकेत देते हैं कि औपचारिक कक्षा-शिक्षा से अलग, व्यावहारिक प्रशिक्षण छात्रों को अपनी रुचियों, क्षमताओं और लक्ष्यों पर पुनर्विचार का अवसर देता है। यह निष्कर्ष सिंह (2020) के विचार का समर्थन करता है, जिन्होंने कहा था कि आत्मबोध भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रथम स्तंभ है तथा आत्म-निरीक्षण से आत्म-विश्वास बढ़ता है। वगानी एवं गौर (2021) के अध्ययन से भी यह संगति रखता है। तालिका 5 में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित छात्रों के तुलनात्मक स्कोर दर्शाते हैं कि कौशल-योजनाएँ केवल तकनीकी दक्षता ही नहीं, बल्कि संचार, टीम-कार्य और उद्यमशीलता-दृष्टिकोण जैसे "सॉफ्ट-स्किल्स" भी विकसित करती हैं। डिजिटल कौशल में सबसे अधिक अंतर पाया जाना यह दर्शाता है कि कोविड-19 के बाद आरम्भ की गयी ऑनलाइन प्रशिक्षण-पद्धतियों ने झाँसी जैसे क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव छोड़ा है। यह मेहरोत्रा (2014) के उस तर्क का व्यावहारिक प्रमाण है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करना अनिवार्य है।

तीसरा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि प्रशिक्षण-पूर्णता दर (80.4%) के बावजूद प्लेसमेंट दर (31.5%) कम रही। यह राष्ट्रीय औसत 56.76% (एन.एस.डी.सी., 2020) से नीचे है तथा रामासामी एवं गोपाल (2020) के क्षेत्रीय असमानता-तर्क की पुष्टि करता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक आधार सीमित है, इसलिए प्रमाणित युवाओं को स्थानीय रोज़गार अवसर नहीं मिल पाते। यदि हाल ही में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण और रक्षा गलियारे जैसी पहलें ज़मीन पर उतरती हैं, तो यह स्थिति बदल सकती है। तालिका 6 के परिणाम बताते हैं कि छात्र प्रशिक्षक-गुणवत्ता को सबसे महत्त्वपूर्ण कारक मानते हैं, जबकि प्लेसमेंट-सहायता को सबसे कमज़ोर। यह जोशी एवं पाण्डेय (2021) के निष्कर्ष का समर्थन करता है। राव (2021) द्वारा बतायी गयी क्षेत्रीय असमानता तथा शर्मा (2020) द्वारा रेखांकित लिंग-भिन्नताएँ झाँसी में भी देखी गयीं पुरुष छात्रों ने तकनीकी पाठ्यक्रमों में अधिक भागीदारी की, जबकि महिलाएँ ब्यूटी-वेलनेस तथा सिलाई जैसे पाठ्यक्रमों तक सीमित रहीं। यह संरचनात्मक भेदभाव योजनाओं के समावेशी डिज़ाइन की माँग करता है। समग्र रूप से, शोध की परिकल्पना "सरकारी कौशल योजनाओं में भागीदारी छात्रों के आत्मबोध एवं कौशल को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है" सांख्यिकीय रूप से सिद्ध होती है। फिर भी प्रभावशीलता को अधिकतम करने हेतु जागरूकता अभियान, उद्योग-संलग्नता, स्थानीय रोज़गार-सृजन तथा प्रशिक्षण-गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान आवश्यक है (मेहरोत्रा, 2014; पाइल्ज़ एवं रेगेल, 2021)।

7. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन ने झाँसी जनपद के 320 स्नातक छात्रों के अनुभवजन्य आँकड़ों के आधार पर सिद्ध किया है कि सरकारी कौशल विकास योजनाएँ आत्मबोध एवं कौशल-निर्माण में निःसंदेह सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। पी.एम.के.वी.वाई. की जागरूकता संतोषजनक है, परंतु अन्य योजनाओं तक सूचना-प्रसार अपर्याप्त है। प्रशिक्षण के बाद आत्मबोध और सभी कौशल-आयामों में सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण सुधार देखा गया, जो योजनाओं की मूल अवधारणा को सही ठहराता है। साथ ही प्लेसमेंट दर का निम्न स्तर तथा उद्योग-संलग्नता की कमी प्रमुख चिंताएँ हैं। नीति-निर्माताओं को महाविद्यालय-स्तर पर कैरियर मार्गदर्शन कक्ष, स्थानीय उद्योग-शिक्षा भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयाँ तथा महिला-केंद्रित विशेष पाठ्यक्रम संचालित करने चाहिए। बुंदेलखंड क्षेत्र की विशिष्ट कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के अनुरूप पाठ्यक्रम-डिज़ाइन समय की माँग है। इन सुधारों से झाँसी के युवा सही अर्थों में आत्मनिर्भर भारत के निर्माता बन सकेंगे।

संदर्भ-सूची

1 अग्रवाल, टी. (2019). भारत में कौशल विकास: मुद्दों और चुनौतियों का परीक्षण। *एशियाई लोक नीति पत्रिका, 12*(3), 245–260। https://doi.org/10.1080/17516234.2019.1576213

2 एन.एस.डी.सी. (2020). *पी.एम.के.वी.वाई. 2.0 निगरानी रिपोर्ट*। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। https://nsdcindia.org/pmkvy-overview

3 केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय. (2021). *वार्षिक रिपोर्ट 2020–21*। भारत सरकार, एम.एस.डी.ई.। https://msde.gov.in/sites/default/files/2021-12/Annual%20Report%20English%202020-21.pdf

4 गणेशन, एम. के., एवं वेथिराजन, सी. (2020). भारत में कौशल विकास पहलें और रोज़गार के अवसर। *यूनिवर्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, 1*(3), 47–55। https://ssrn.com/abstract=3827893

5 ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2020). *वार्षिक रिपोर्ट 2019–20: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.)*। भारत सरकार। http://ddugky.gov.in

6 जोशी, ए. के., एवं पाण्डेय, के. एन. (2021). हरियाणा में पी.एम.के.वी.वाई. प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता, धारणा और युवा-संगठन। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट, 11*(11), 2528–2537। https://ssrn.com/abstract=3785102

7 झाँसी जिला प्रशासन. (2021). *झाँसी का जिला सांख्यिकीय हस्तपुस्तक*। उत्तर प्रदेश सरकार। https://jhansi.nic.in/demography/

8 पाइल्ज़, एम., एवं रेगेल, जे. (2021). भारत में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण: बाह्य परिप्रेक्ष्य से सम्भावनाएँ और चुनौतियाँ। *मार्जिन: द जर्नल ऑफ़ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, 15*(1), 101–121। https://doi.org/10.1177/0973801020976606

9 पुहान, आर. आर., एवं माल्ला, एल. (2024). शैक्षिक संस्थाओं में छात्रों एवं शिक्षकों के बीच आत्मबोध विकसित करने की रणनीतियाँ। *यूनिवर्सल लाइब्रेरी ऑफ़ आर्ट्स एण्ड ह्यूमैनिटीज़, 1*(1), 45–50। https://doi.org/10.70315/uloap.ulahu.2024.0101009

10 मेहरोत्रा, एस. (2014). *भारत की कौशल चुनौती: जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन हेतु व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सुधार*। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

11 मेहरोत्रा, एस., गांधी, ए., एवं साहू, बी. के. (2014). क्या भारत की टी.वी.ई.टी. प्रणाली तीव्र आर्थिक विकास की चुनौती का सामना कर रही है? एस. मेहरोत्रा (सं.), *भारत की कौशल चुनौती* (पृ. 1–35) में। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

12 मोंडल, एस., एवं अन्य. (2023). उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों में आत्मबोध-कौशल। *एशियन जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एण्ड सोशल स्टडीज़, 43*(4), 22–29। https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v43i4942

13 राज, आर., एवं शर्मा, पी. (2021). कौशल विकास योजनाओं में मीडिया की भूमिका और जागरूकता-सृजन: पी.एम.के.वी.वाई. का अध्ययन। *जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, 40*(3), 312–328। https://doi.org/10.25175/jrd/2021/v40/i3/164226

14 रामासामी, एम., एवं गोपाल, एन. (2020). पी.एम.के.वी.वाई. के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ: एक क्षेत्रीय मूल्यांकन। *जर्नल ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 5*(1), 19–29। https://doi.org/10.11648/j.jppa.20200501.13

15 राय, ए., एवं जोशी, बी. (2017). उत्तर प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रमों का एक अनुभवजन्य अध्ययन। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस एण्ड रिसर्च, 4*(11), 558–566। http://ijetsr.com/images/short_pdf/1511690720_558-566-ieteb812_ijetsr.pdf

16 राव, एम. (2021). जीवन-कौशल शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताएँ: भारत से अंतर्दृष्टि। *इंडियन जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च, 10*(2), 88–104। https://doi.org/10.32381/IJER.2021.10.02.5

17 वगानी, आर., एवं गौर, पी. (2021). महाविद्यालय छात्रों के बीच आत्मबोध और कल्याण: एक अनुभवजन्य अनुसंधान। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंडियन साइकोलॉजी, 9*(2), 1265–1278। https://doi.org/10.25215/0902.131

18 शर्मा, एन. (2020). महाविद्यालय छात्रों के जीवन-कौशल में लैंगिक भिन्नताएँ। *जर्नल ऑफ़ जेंडर स्टडीज़, 28*(4), 345–360। https://doi.org/10.1080/09589236.2019.1567456

19 शिक्षा मंत्रालय. (2021). *अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2020–21*। भारत सरकार। https://aishe.gov.in/aishe-final-report/

20 सिंह, पी. (2020). आत्मबोध एवं लॉकडाउन, कौशल निर्माण एवं लॉकडाउन। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंडियन साइकोलॉजी, 8*(2), 339–346। https://doi.org/10.25215/0802.245

Cite this Article:

रहीस अली[1], डॉ. धर्मेंद्र सिंह[2]," स्नातक छात्रों के आत्मबोध और कौशल निर्माण में सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता: झाँसी का एक विश्लेषण" The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp.258–265,Volume-04, Issue-04, January-2026, https://theresearchdialogue.com/

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

रहीस अली[1], डॉ. धर्मेंद्र सिंह[2]

For publication of Research Paper title

स्नातक छात्रों के आत्मबोध और कौशल निर्माण में सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता: झाँसी का एक विश्लेषण

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-04, Month January, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/